

"C-6"  
B.Ed

## स्वतन्त्र भारत में स्त्री-शिक्षा WOMEN EDUCATION IN INDEPENDENT INDIA

स्वतन्त्र भारत में नारी की सामाजिक परिस्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा था जिन बन्धनों में वह बँधी हुई थी वे शरीर, शक्ति, दौलत हट जा रहे थे। जिन स्वतन्त्रता से उसे वंचित कर दिया गया था वह उसे पुनः प्राप्त हो रही थी। उसके सम्बन्ध में उरुषो का दृष्टिकोण बदल रहा है। उनकी सन्ध्याएँ बदल रही हैं। भारतीय समाज ने भी नारी को समकक्षता प्रदान करते हुए घोषित किया है - "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग जन्म-स्थान या इनमें किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा"।

उपरि अंकित सभी

तथ्यों के फलस्वरूप स्वतन्त्र भारत में नारी जाति ने कदम बढ़ाए हैं। उन्हें अपने वास्तविक महत्व को जानना और पचासना शुरू कर दिया है।

NATIONAL COMMITTEE ON WOMEN'S  
EDUCATION - 1958

भारत सरकार ने सन् 1958 में स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की नियुक्ति की। इस समिति में देशमुख समिति भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य - स्त्री-शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करना था। समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और निम्नांकित सुझाव दिए -

1. केन्द्रीय सरकार को स्त्री शिक्षा को कुछ समय के लिए एक विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसके प्रसार का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।

2. केन्द्रीय सरकार को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित अवधि में हरी शिक्षा का विकास एवं वित्त देना चाहिए ।
3. केन्द्रीय सरकार को सब राज्यों के लिए हरी-शिक्षा के वित्त की नीति निर्धारित करनी चाहिए और उन्हें इस नीति का अनुसरण करने के लिए प्रेरणा देना चाहिए ।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में हरी-शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए और केन्द्रीय सरकार को प्रसार सम्बन्धी समस्त व्यय का भार ~~अपने~~ अपने उपर लेना चाहिए ।
5. पुरुषों एवं स्त्रियों की शिक्षा में विषमता को शायदीय समाप्त करके दोनों की शिक्षा में समानता स्थापित की जानी चाहिए ।

6. केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय की स्त्री शिक्षा की समन्वयात्मक पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद नामक एक पृथक इकाई की वृद्धि करनी चाहिए।
7. राज्यों में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए बालिका एवं स्त्री शिक्षा की राज्य परिषदों का निर्माण किया जाना चाहिए।
8. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं को शिक्षा की अधिक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।—